International Referred Research Journal, February, 2012. ISSN- 0974-2832, RNI-RAJBIL 2009/29954;VoL.III *ISSUE-37

शोध पत्र- समाजशास्त्र

उदारीकरण के भंवरजाल मे छत्तीसगढ़ के आदिवासी

* डॉ. अंज़ शक्ला ** स्वाती शर्मा

*- ** डी.पी. विप्र महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)

February, 2012

नवोदित छत्तीसगढ़ आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र हैं। यहां की कुल जनसंख्या 5,07,25,956 है। यहां की लगभग एक तिहाई से अधिक 32.46 प्रति'ात जनसंख्या अनुसूचित जनजातियों की है। यहां जनसंख्या की दृष्टिकोण से आदिवासयों का वितरण असमान है। पहली पंक्ति में दंतेवाड़ा में 79 प्रति'ात, ज'ापुर में 65.36 प्रति'ात, बस्तर में 66.5 प्रति'ात है, जबकि दूसरी पंक्ति में सरगुजा 56.70 प्रति'ात, कांकेर 55.72 प्रति'ात, कोरिया 44 प्रति'ात तथा कोरबा में 43 प्रति'ात है। तीसरी पंक्ति में रायगढ़ 36.81 प्रति'ात, महासमुंद 28.10 प्रति'ात, धमतरी 27.26 प्रति'ात, बिलासपुर 20.49 प्रति'ात है। सबसे कम जनसंख्या रायपुर 13.11 व 12.12 प्रति'ात जांजगीर–चांपा में है।

छत्तीसगढ़ में 42 प्रकार की जनजातियां संविधान के अंतर्गत पाई जाती है जिसमें – 1. अगरिया, 2. अंध, 3. बैगा, 4. भैना, 5. पांडो, 6. भतरा, 7. भील या भिलाला, 8. भील मीना, 9. भुजिया, 10. बियार, 11. बिंझवार, 12. बिरहुल या विरहोर, 13. डामौर, 14. धनवार, 15. गड़वा, 16. गोंड़, 17. हलबा, 18. कमार, 19. कोरकु, 20. कंवर, 21. खेरबार, 22. खरिया, 23. कौंड़, 24. कोल, 25. कोलाप, 26. कोटक, 27. कोरवा, 28. मांझी, 29. मंझवार, 30. मवासी, 31. मुण्डा, 32. नागे'िया, 33. उरांव, 34. पांव, 35. परधान, 36. पारधी, 37. पात्रा, 38. सहारिया, 39. सिओंता, 40. सौर, 41. संवरा एवं 42. सोर। छत्तीसगढ़ में गोड़ों की जनसंख्या सर्वाधिक है, बैगा, कमार जैसी जनजातियां अत्यधिक पिछड़ा हुआ जनजाति है।

भारत में औद्योगिक संस्कृति के पदार्पण के बाद यहां की जनजातियों के जीवन में अनेक नयी समाजिक, आर्थिक, धार्मिक, सांस्कृतिक तथा राजनीतिक द'ाओं ने भारी प्रभाव डाला है। खासकर के जब से उदारीकरण की प्रक्रिया पर जोर दिया गया है। दूर–दराज में बसे आदिवासी समाज भी इससे प्रभावित हुआ है। मीडिया का प्रभाव समस्त आदिवासी समाज में दिखाई देता है। भू–गर्भशास्त्रियों ने आदिवासी निवास स्थलों पर खनिज भंडार को खोज कर औद्योगीकरण के साथ–साथ जीवकोपार्जन को लेकर नगरों की तरफ पलायन करने लगे हैं। बेलाडीला में लौह अयस्क, कोरबा क्षेत्र में कोयला खदान, सीपत एन.टी. पी.सी., भिलाई इस्पात संयंत्र, विद्युत उत्पादन एवं सीमेंट उत्पादन आदि है। आज भी छत्तीसगढ़ के आदिवासी सामाजिक, आर्थिक परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है। डॉ. हीरालाल 'ाुक्ला ''सार्वभौमिकता तथा उदारीकरण पर जोर देने वाली नयी आर्थिक नीति से आदिवासी पुरूषों तथा स्त्रियों के जीवन पर गंभीर परिणाम आ सकते हैं। यद्यपि उन नीतियों के नतीजों का सही स्वरूप अभी तक मजबूत नहीं हकया गया है। फिर भी राज्य सरकार पहले से ही उनके विकास में निवे'ा के लिये बहुराष्ट्रीय संस्थाओं को आमंत्रित कर रही है। ऐसी स्थिति में 'ाासकीय नियमों के अंतर्गत आदिवासियों की विकास प्रक्रिया पूरी तरह प्रभावित हो सकती है। आर्थिक उदारीकरण न केवल उनके समाधान की नींव को हिला देगा बल्कि उनकी सामाजिक और आर्थिक संवेदन'ाीलता को भी प्रभावित करेगा।''[1]

उदारीकरण ने जनजातियों के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जिसके सकारात्मक एवं नकारात्मक प्रभावों का अध्ययन 'ाोध का प्रमुख उद्दे'य रहा है।

उदारीकरण ने आदिवासी समाज पर जो सकारात्मक प्रभाव डाला, उन्हें हम निम्न आधार पर समझ सकते हैं –

1. उदारीकरण की घटनाओं ने आदिवासियों के सामाजिक जागरूकता तथा चेतना के दृष्टिकोण में बड़ा परिवर्तन ला दिया है। ये परिवर्तन जो पहले बहुत धीमी गति से चल रही थी आज तीव्र हो गयी है। बिखरा हुआ जनजातीय समाज अपनी भाषा, संस्कृति, धर्म एवं नेतृत्व को लेकर जागरूक है। समय–समय पर आदिवासी संगठन बनाना आदिवासी कल्याण के लिए आवाज उठाना इसके उदाहरण हैं।

2. आपसी भाईचारा एवं सामाजिक एकीकरण के प्रभाव को बढ़ावा मिला है। कुछ समय पहले आदिवासी समाज भौगोलिक एवं सांस्कृतिक पृथकता के कारण अलग–अलग बंटे हुये थे, परन्तु उदारीकण का रचनात्मक प्रभाव यह पड़ा है कि वे रोजगार के लिए अब उद्योगों में काम करने के लिए एक साथ रहने लगे। साथ–साथ रहते और अत्याचार को सहन करते आज भी इनमें जातीय स्तर पर भाईचारा, सौहार्द्र व अस्मिता का नया एहसास आया।

आर्थिक एवं राजनैतिक घटनाओं से जुड़े हुए आदिवासी समाज की राजनैतिक चेतना एवं महत्वाकांक्षाओं में भी परिवर्तन आया। लोकतांत्रिक समाज व्यवस्था में जनजातीय समाज को राजनीति में आरक्षण देकर मुख्य धाराओं से जोड़ने का प्रयास किया गया। आज राजनीति के क्षेत्र में आदिवासी नेतृत्व छत्तीसगढ़ सरकार को प्रभावित कर रहा है।

ि'ाक्षा के क्षेत्र में जागरूकता आया है। ि'ाक्षा के पर्याप्त सुविधाएं होने के कारण अधिकां'ा जनजातियों में ि'ाक्षा के प्रति

रूचि बढ़ती जा रही है। उरांव समाज में ि"क्षा के प्रति रूचि बढ़ती जा रही है। उरांव समाज में ि"क्षा के साथ गति'ाीलता स्पष्ट दिखाई देता है। सरकार द्वारा आदिवासी परिवार के लिए अधिक से अधिक ि"क्षा को प्रोत्साहन देने के कारण केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार की 'ाासकीय कर्मचारियों में जनजातीय कर्मचारियों की संख्या बढ़ी है।

रोजगार के अवसरों में वृद्धि हुई है। उदारीकरण ने रोजगार के नये–नये अवसर प्रदान किये हैं। आज जनजातीय युवक अनेक क्षेत्रों में रहते हैं जैसे इंजीनियरिंग, कम्प्यूटर, डाक्टरी, लिपिक, सुपरवाईजर आदि कई क्षेत्रों में प्र"िाक्षण ले रहे हैं और काम कर रहे हैं, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति समाज के मध्यम वर्ग के समान बन गयी है।

उदारीकरण में बाजारवाद को बढ़ावा दिया जा रहा है और जनजातीय ि"ाल्प कला को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बहुत अच्छा प्रतिसाद मिला है। बस्तर ि"ाल्प कलाओं द्वारा उत्पादित समान बहुत मंहगे दामों में वि'ाव बाजार में बिक रहे हैं।

उदारीकरण के कारण छत्तीसगढ़ के अनेक आदिवासी क्षेत्रों के नेतृत्व क्षमता में व्यापक परिवर्तन आया है। परम्परागत नेतृत्व मुखिया की जगह पर राजनैतिक नेतृत्व का महत्व बढ़ा है। मांझी, चालकी, सिरहे, गुनिया, लेस्के, ओझा, महतो आदि पारंपरिक नेतृत्व के उदाहरण हैं। परन्तु आज अपने कुशलता से एजेंट, शिक्षक, सरकारी कर्मचारी, एन.जी.ओ., स्थानीय विधायक नेतृत्व के क्षेत्र में है। कांग्रेसी नेता श्री रामपुकार सिंह, भाजपा नेता श्री बलिराम कश्यप, श्री केदार कश्यप, श्री रामविचार नेतामा, श्री ननकी राम कंवर आदिवासी नेतृत्व के उदाहरण हैं।

बिलासपुर जिले के भैना, कंवर, गोंड़, जशपुर, रायगढ़ के उरांव जैसे जनजातियों के अध्ययन से पता चलता है कि इनके सामाजिक, सांस्कृतिक, पारिवारिक संरचना व आकार, वैचारिक मूल्यों, रहन–सहन व वेशभूषा आधुनिकता का प्रभाव पड़ा है। इन जनजातियों ने अपने वेशभूषा, खानपान में आधुनिकता को काफी हद तक समावेश किया है।

डॉ. श्यामाचरण दुबे ने अपनी पुस्तक 'द कमार' में छत्तीसगढ़ के कमार जनजातियों के जीवन संगठन का विस्तृत अध्ययन किया है। डॉ. मजूमदार एवं मदान ने अपने 'एन इन्ट्रोडक्शन टू सोशल एन्थ्रोपोलॉजी में बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश एवं बंगाल के जनजातियों का विशुद्ध वर्णन किया है। हीरालाल एवं रसेल ने भैना जनजाति का अध्ययन किया है। डॉ. वी.वी. नायक ने अपने पुस्तक 'बारह भाई बिंझवार' में बिंझवार जनजाति का विस्तार से उल्लेख किया है। प्रोफेसर हीरालाल शुक्ल ने आदिवासी अस्मिता और विकास में आदिवासी विकास, संस्कृति एवं समस्याओं का क्रमबद्ध वर्णन किया है।

उदारीकरण ने जहां एक ओर आदिवासी जनजातियों पर सकारात्मक प्रभाव डाला है, वहीं इनका दूसरा पहलू नकारात्मक है। अनेक समाजशास्त्रियों के अध्ययनों से यह बात सामने आई है कि उदारीकरण के नीति के कारण आदिवासी अस्मित खतरे में पड़ गई है। जनजातीय संस्कृति जिसे पूर्ण संस्कृत कहा जाता है, आज चारों तरफ निजीकरण का बोलबाला है। निजीकरण छत्तीसगढ़ की गरीब आदिवासी जनता का विकल्प कभी नहीं हो सकता। पीड़ित आदिवासी जनता शिक्षा, स्वास्थ्य आदि के क्षेत्र में निजीकरण की सोंच भी नहीं कर सकता।

आज की व्यवस्था वैश्वीकरण पर आधारित होने जा रही है। वैश्वीकरण में विकास की आदिम संभावनाएं नहीं रहती। आज लोग मानने लगे हैं कि तकनीकी के द्वारा नियंत्रित आदिवासी अर्थशास्त्र तथा तकनीकी के द्वारा पोषित आदिवासियों की आकांक्षाएं विकास का सहीं मॉडल है, परन्तु यह ठीक नहीं है। वैश्वीकरण के कारण आज समाज आदिवासियों की ज्ञान शक्ति व चेतना को धुंधलाने का प्रयास कर रही है।

प्रो. हीरालाल शुक्ला के अनुसार – ''यदि हम मध्यप्रदेश के दो सौ वर्षों की जनजातियों का शोध परक सामग्री का विश्लेषण करें तो ऐसा कहीं लगेगा कि अपने ही देश के बंधु–बांधवों के बीच में ही मानवशास्त्री शोध करते आ रहे हैं। इन्होंने पश्चिम के मानव विज्ञान का अनुसारण कर जनजातियों के प्रति असहिष्णुता विकसित कर ली है।''(2)

उदारीकरण के कारण जनजाति समाज में पारिवारिक एवं सामाजिक विघटन बढ़ा है। गोंड़, कंवर, उराव, भैना, भूमिया जैसे जनजातियां उद्योगों की ओर आकर्षित हो रहे हैं। स्त्रियां काम की तलाश में नगरों की राह पकड़ रही है। नवाचार के कारण नये मूल्यों, विचारों को अपनाने के कारण आज आदिवासी परिवार एवं समाज विघटन के कगार पर है।

आर्थिक समस्याएं मुंह बनाये खड़ी है। आधुनिक सभ्यता आदिवासी से उनकी परंपरागत खेती, वनोपज एवं शिकार जो उनके अर्थव्यवस्था के प्रमुख अंग हैं, जो उनसे छीन लिया गया। ऊपर से ठेकेदारों, उद्योगपतियों का आदिवासी अर्थव्यवस्था में हस्तक्षेप बढ़ गया है। देश के आदिवासियों की मुख्य समस्या विस्थापन की रही है। यह समस्या सदियों से जारी है। अंग्रेजों ने आदिवासियों के जंगल में प्रवेश पर रोक लगा दिया था। आजाद भारत सरकार ने भी वही नीतियां चलाई। ''सन् 1960–61 में ढेबर आयोग (अनुसूचित जनजाति आयोग) ने इस सरकारी नीति पर टिप्पणी की थी।''(3)

''इस तरह आदिवासी पहले जो अपने को वनपति समझता आया था, एक सुनियोजित प्रक्रिया द्वारा एक रैयत के दर्जे पर उतार दिया गया और वन विभाग की दया पर छोड़ दिया गया है। उनके बसाएं गांव वन के ही मौलिक अंग न रहकर विभागीय वरदहस्त पर टिक गया है। जनजातियों के परंपरागत वन अधिकार की मान्यता की इतिश्री कर दी गई है, जो 1894 से अधिकार और विशेषाधिकार माने गये थे। वे 1952 में अधिकार और रियायत में तब्दील हो गयी। अब तो उन्हें रियायत मात्र समझा जाता है।''(4)

छत्तीसगढ़ के सुरम्य वन प्रदेश पिछले 3 दशकों से नक्सलवाद के ताण्डव से अशांत है। नक्सली आतंक से केवल

आदिवासी ही नहीं प्रशासन भी परेशान है। दंतेवाड़ा, जगदलपुर, राजनांदगांव, सरगुजा जिलों में नक्सलियों का आतंक बढ़ता ही जा रहा है। बिलासपुर, रायपुर जैसे नगरों में भी उनके छिपने की घटना का पता चलता है। नक्सली अपने निहित स्वार्थ के लिये आदिवासियों को हंथियार बना रहे हैं।

उदारीकरण का आदिवासी समाज पर कुछ प्रकार्यात्मक प्रभाव पड़ा है। उनके विकास के रास्ते खुले, उन्हें नौकरी में स्थान मिला, राजनीति में पदार्पण हुआ, शिक्षा के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में उन्हें अवसर मिला। परन्तु नकारात्मक प्रभाव भी बहुत भारी पड़ा। भू–मण्डलीकरण के बहाने तमाम बहुराष्ट्रीय कम्पनियां दूर वन प्रांतों में पहुंच रहे हैं और परंपरागत आदिवासी समाज की व्यवस्था मिटती जा रही है। आदिवासी की प्रमुख पहचान मिटते जा रहा है। सांस्कृतिक अस्मिता, मानसिक संघर्ष व तनाव बढ़ रहे हैं। उनके जंगल जमीन पर से अधिकार छीन लिया गया है। आज भी आदिवासी अपने ही विकास के लिए अस्तित्व तलाश रही है।

आज शोध का चिंतनीय विषय यही है कि जनजातीय समाज के लिए विकास की विधि ऐसी हो जिससे उनका प्रकार्यात्मक विकास हो सके। वे अपने सांस्कृतिक पहचान को बनाये रखते हुए देश के विकास की मुख्य धारा से जुड़ जाएं।

संदर्भ ग्रंथ

1. शुक्ल, हीराला : आदिवासी अस्मिता और विकास, मध्य प्रदेश हिन्दी ग्रंथ अकादमी, भोपाल, 1997. 2. दुबे, श्यामाचरण : ''दी कमार'', लखनऊ प्रेस, 1951.3. मजूमदार एवं मदान : सामाजिक मानवशास्त्र परिचय, नेशनल पब्लिशिंग हाउस, दिल्ली, 1984.4. एलविन, बेरियर : दे मुरिया एण्ड देयर घोटुल, आक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, लंदन, 1947.5. त्रिपाठी, संजय एवं चंदन : छत्तीसगढ़ वृहद् संदर्भ, उपकार प्रकाशन, 2002.6. गुप्ता, रमणिका : आदिवासियों की पहचान मिटाता आधुनिक विकास, हाशिये की आवाज, दिल्ली, 2011.